पत्र सं० वन भूमि– 23/14– 4145(8)/प०व०

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

यू०एस० झा,
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/गृह विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पटना 15, दिनांक :– 26-8-14

विषय : वन (संरक्षण) अधि० 1980, के तहत वनभूमि के अपयोजन की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाने वाली कार्रवाई की संक्षिप्त विवरणी–आवश्यक तथ्यों की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विकास कार्यों के लिये वनभूमि के अपयोजन की त्वरित स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया अभिलेखों का चेक लिस्ट विभिन्न स्तर पर प्राप्त शक्तियाँ एवं प्रपत्र में प्रविष्टि की प्रक्रिया के साथ प्रपत्र का एक सेट संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

20/08/14

(यू० एस० झा)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

E:\Ashok 2014\A.S U.S. Jha\Letter_20-08-2014_23 van bhumi.docx

(214)

(2)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

प्रथम तल, एन०एच० भवन, विश्वेश्वरैया परिसर, बेली रोड, पटना–800 015

संख्या– FC–375

AS

प्रेषक,

एस० एस० चौधरी, भा०व०से०
मुख्य वन संरक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

प्रधान सचिव का कार्यालय
पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार
दिनांक 24/7/14

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना–15, दिनांक 24/07/2014

विषय– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अपयोजन की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाने वाली कार्रवाई की संक्षिप्त विवरणी– आवश्यक तथ्यों की जानकारी

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विकास कार्यों के लिये वन भूमि के अपयोजन की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया, अभिलेखों का चेक लिस्ट, विभिन्न स्तर पर प्राप्त शक्तियाँ एवं प्रपत्र में प्रविष्टि की प्रक्रिया के साथ प्रपत्र का एक सेट संलग्न कर भेजी जा रही है।

2. इस विषय की जानकारी के लिये पूरी विवरणी को विकास प्रभाग के विभाग यथा जल संसाधन, लघु सिंचाई, ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, स्वाथ्य विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग आदि को भेजी जा सकती है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
24/7/14
मुख्य वन संरक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन / फैक्स न०–0612–2545109 ई–मेल ccfwp.bih@hotmail.com

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत समर्पित किये जाने वाले प्रस्तावों से संबंधित सामान्य जानकारी।

1. प्रपत्र Form-I के सभी कंडिका में अंकित कर एवं Part-II, Part-III, Part-IV एवं Part-V रिक्त प्रपत्र को संलग्न करते हुए प्रस्ताव आठ प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के कार्यालय, पटना में जमा करना होता है।

2. प्रपत्र Form-I में प्रवृष्टि का तरीका एवं चेक लिस्ट संलग्न है।

3. मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार कार्यालय द्वारा वन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी को प्रपत्र–II एवं प्रपत्र–III एवं स्थल निरिक्षण करने हेतु भेजी जाती है।

4. इसके उपरान्त नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार कार्यालय द्वारा प्रस्ताव पर Stage-I (सैद्धान्तिक स्वीकृति) प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाती है।

5. प्रस्ताव पर Stage-I (सैद्धान्तिक) स्वीकृति मिलने के उपरान्त उसमें निहित कंडिका का कंडिकावार अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी को करनी होती है।

6. Stage-I की कंडिका में मुख्यतः NPV, CA एवं PCA (अगर परियोजना निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हो गया है तो) की राशि जमा करनी होती है।

7. इसके अतिरिक्त सभी कंडिका में निहित शर्त्तों के अनुपालन करने का Undertaking समर्पित करना होता है।

नोट– NPV- Net Present Value, CA- Campansatry Afforestration, PCA- Penal Campansatry Afforestration

खण्ड–II

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव समर्पित करने हेतु जाँच–पत्र (चेक लिस्ट)

1. निर्धारित प्रपत्र– सभी स्तम्भों में प्रविष्टियाँ अंकित की जाय और वांछित अभिलेख संलग्न किये जाये। यदि किसी स्तम्भ में प्रविष्ट करना आवश्यक नहीं हो तो इसका भी उल्लेख कर दिया जाय। (यथा, लागू नहीं/शून्य/किसी अन्य क्रमांक में उल्लिखित आदि)

(क) योजना की संक्षिप्त विवरणी जिसमें Project formulation, प्रशासनिक स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति की संख्या एवं तिथि और स्वीकृति करने वाले प्राधिकार/योजना लागू करने वाली संस्था/वित्तीय संस्थान का उल्लेख

(ख) अपयोजन के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल यथा संम्भव (पैमाइश के साथ)

(ग) पथ की कुल लंबाई (आरम्भिक बिन्दु से अंतिम बिन्दु तक, कि0मी0 स्थल के नाम के साथ)

(घ) परियोजना हेतु उपयोग किये जाने वाले भूमि का प्रयोजनवार विवरणी purposewise break up of landuse (Forest as well as non-forest land)

2. (क) अपयोजित होने वाली वन भूमि, समीप के वनों का सीमांकन दर्शाते हुये सर्वे ऑफ इंडिया के मूल टोपोशीट पर 1:50,000 माप में नक्शा। (यदि 1:50,000 माप का नक्शा उपलब्ध न हो तो 1"=1mile ;k 1"=4 mile या कोई अन्य उपयुक्त नक्शा)

(ख) अपयोजन होने वाली वन भूमि का स्तम्भ द्वारा अस्थायी सीमांकन।

3. अपयोजित होने वाले क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों की गणना **सूची का सारांश** (प्रजाति–वार एवं घेरा–वार)

नोटः– (क) 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के लिए पूर्ण गणना।

(ख) वृहत क्षेत्र के लिये स्टैण्र्ड सैम्पलिंग विधि द्वारा गणना की जायेगी अधिक प्रजाति के वृक्षों के लिये सैम्पलिंग Stratified Sampling Technique द्वारा की जायेगी।

4. योजना की स्वीकृति के संबंध में सरकार का आदेश (सरकारी योजनाओं के लिये)

5. राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लगाये जाने वाले शर्त्तो के अनुपालन के संबंध में प्रयोक्ता प्राधिकार द्वारा समर्पित **वचनबद्धता प्रमाण–पत्र**

6. लागत लाभ विश्लेषण (Cost benefit analysis) – समतल क्षेत्र में 20 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के अपयोजन के मामलों में (सड़क, पारेषण लाईन, सिंचाई परियोजनाएँ, खनन कार्य, रेलवे इत्यादि सहित)।

7. अपयोजित होने वाले वन भूमि का GPS Reading Geo referenced Co-Ordinate Map संलग्न करना अनिवार्य।

8. वनाधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण–पत्र संबंधित जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करना। रैखिक परियोजनाओं के लिये प्रपत्र–I तथा प्राकृतिक वन के लिये प्रपत्र–II में प्रमाण पत्र देना है। प्रपत्र संलग्न है।

9. यदि अपयोजित होने वाली वन भूमि प्राकृतिक वन में है, तो अपयोजित होने वाली वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि दिया जाना है, उसकी विवरणी, मानचित्र, DGPS Reading, 1:50 000 स्केल का मानचित्र पर Geo-referencing कर स्थल दर्शाया जाना, जमीन का स्थानान्तरण, दाखिल खारिज एवं वन भूमि के रूप में अधिसूचना निर्गत किया जाना (भारत सरकार के परियोजना में इस शर्त्त से छूट दी गयी है)।

10. संलग्न किये गये कागजातों/अभिलेखों की सूची।

11. संलग्न अभिलेखों पर मुहर एवं हस्ताक्षर

खण्ड–III

(वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति की शक्तियाँ एवं स्वीकृति की प्रक्रिया)

1. वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति की शक्तियाँ–

(क) क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर को– 5 हेक्टेयर
(खनन एवं अतिक्रमण छोड़कर)

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर को अनुशंसा के लिये 5–40 हेक्टेयर

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को

(1) खनन एवं अतिक्रमण के सभी मामलें

(2) 40 हे० से अधिक के मामले

2. राज्य सरकार को प्रदत्त शक्ति–

1. सामान्य जिले के लिये– 1 हेक्टयर तक

यह शक्ति निम्नवत् कार्यों के लिये ही दी गयी है–

(i) स्कूल
(ii) डिस्पेन्सरी/अस्पताल
(iii) विद्युत एवं संचार लाईन
(iv) पीने के पानी की व्यवस्था
(v) जल/वर्षा जल हार्वेस्टिं ढ़ाँचा
(vi) लघु सिंचाई नहरें
(vii) गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत
(viii) कुशलता उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
(ix) विद्युत सब–स्टेशन
(x) संचार पोस्ट
(xi) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन/आउट पोस्ट/बॉर्डर आउटपोस्ट/वाच टावर।

2. उग्रवाद प्रभावित जिले में (15 जिला) 5 हेक्टेयर तक

(अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सीतामढ़ी)

कंडिका संख्या 2.1 में अंकित (11) कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों के लिये भी शक्ति प्रदत है–

1. ग्रामीण पथ का निर्माण एवं भूमिगत ऑप्टिकल फाइवर के बिल/टेलीफोन लाईन/पीन के पानी की सप्लाई लाईन।

3. प्रत्येक परियोजना के लिये प्रति हे० अधिकतम 50 वृक्षों के पातन की आवश्यकता की स्थिति में ही इस शक्ति का उपयोग राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है।

4. इस शक्ति का उपयोग राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी आश्रयणी/सुरक्षित क्षेत्र में नहीं हो सकता है। आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित अपयोजन का प्रस्ताव सर्वप्रथम मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, कार्यालय में समर्पित होता है। वहाँ से राज्य वन्यप्राणी पर्षद् की अनुशंसा प्राप्त की जाती है तत्पश्चात् केन्द्रीय वन्यप्राणी पर्षद की अनुशंसा प्राप्त कर माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ही वन भूमि अपयोजन का विषय नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के पास वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अंतिम रूप से अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित की जाती है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से निम्नलिखित मामलों में राज्य वन्यप्राणी पर्षद्, केन्द्रीय वन्यप्राणी पर्षद से स्वीकृति प्राप्त करने की वाध्यता समाप्त कर दी गयी है। इन मामलों में प्रस्ताव सीधे नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार कार्यालय को समर्पित किया जाना है।

(i) laying of underground drinking water pipelines up to 4 inch diameter,

(ii) lagying of 11 KV distribution lines for supply of electricity to rural areas,

(iii) laying of telephone or optical fiber for providing communication facilities in rural areas,

(iv) Wells, hand pumps, small water tank etc. for providing drinking water facilities to villagers, who are yet to be relocated from the protected area .

In addition to the above, the Anganwadies, government Schools and government dispensaries which are essential for the inhabitants of people who are nearer to these forest areeas shall continue and the Government may carry out construction activities in the forest area for the said purposes withhout there being any cutting or falling of trees.

6. वानाधिकार अधिनियम, 2006 Ministry of Trabal Affairs द्वारा अधिनियमित है इसके तहत वन भूमि के अपयोजन के मामले में प्रपत्र–II में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है जबकि रैखिक परियोजनाओं के लिये वन भूमि के अपयोजन के लिये प्रपत्र–I में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है।

7. रैखिक परियोजनाओं के लिये ग्राम सभा की बैठक कराकर अनुशंसा प्राप्त करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जबकि प्राकृतिक वन भूमि के मामलें में ग्राम सभा की बैठक कराकर बैठक की कार्यवाही संलग्न करते हुए अनुशंसा करना अनिवार्य है।

(209) (10)

खण्ड–IV

प्रपत्र में प्रविष्टि का तरीका

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत समर्पित किये जाने वाला प्रस्ताव प्रपत्र MoEF के वेव साईट पर उपलब्ध है जिसकी एक प्रति इस साथ संलग्न की जा रही है।

2. **संलग्न प्रपत्र के Form-A सभी कंडिका को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरा जाना है जो इस प्रकार है–**

1. Project Details:

(i) इस कंडिका में प्रस्ताव (परियोजना निर्माण) से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी (सारांश सहित), अपयोजित होने वाली वन भूमि को आकलित करते हुए संलग्न किया जाना है।

(ii) इस कंडिका में अपयोजित होने वाली वन भूमि को चिन्हित करते हुए 1:50 000 स्केल का नक्शा संलग्न किया जाना है।

(iii) इस कंडिका में परियोजना निर्माण से संबंधित लागत का विवरण सारांश सहित संलग्न किया जाना है।

(iv) इस कंडिका में वन भूमि में परियोजना लगाने का औचित्य सारांश सहित संलग्न किया जाना है।

(v) इस कंडिका में परियोजना निर्माण से संबंधित लागत लाभ विश्लेषण (Cost benefit analysis) – समतल क्षेत्र में 20 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के अपयोजन के मामलों में (सड़क, पारेषण लाईन, सिंचाई परियोजनाएँ, खनन कार्य, रेलवे इत्यादि सहित) में संलग्न किया जाना है।

(vi) इस कंडिका में परियोजना निर्माण होने में कितने लोगों को कार्य मिलने की संभावना है।

2. इस कंडिका में परियोजन से संबंधित प्रयोजन के लिहाज से कितने वन भूमि की आवश्यकता है को संलग्न किया जाना है।

3. इस कंडिका में परियोजना निर्माण होने होने से अगर किसी लोगों को हटाने की आवश्यकता है तो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है **अगर नहीं हो नहीं अंकित किया जाना है, अगर हॉ तो पुनर्वास योजना संलग्न किया जाना है।**

4. इस कंडिका में परियोजना निर्माण में अगर पर्यावरर्णिक स्वीकृति की आवश्यकता है, तो संबंधित प्राधिकार से इसे प्राप्त कर संलग्न किया जाना है, अगर नहीं हो No अंकित करना है।

5. इस कंडिका में अपयोजित होने वाली भूमि के बदले NPV, CA, PCA एवं Safety Zone के लिये आकलित राशि को देने का बचनबद्धता संलग्न करना होता है (परियोजना के लिये जो लागू हो)।

6. संलग्न किये गये कागजातों/अभिलेखों की सूची।

नोट– NPV- Net Present Value, CA- Campansatry Afforestration, PCA- Penal Campansatry Afforestration

APPENDIX

(See Rule 6)

Form- 'A'

Form for seeking prior approval under section 2 of the proposals by the State Governments and other authorities

PART-I

(to be filled up by user agency)

1. Project details:
   (i) Short narrative of the proposal and project/scheme for which the forest land is required.

   (ii) Map Showing the required forest land, boundary of adjoining forest on a 1:50,000 scale map.

   (iii) Cost of the project:

   (iv) Justification for locating the project in forest area.

   (v) Cost-benefit analysis (to be enclosed).

   (iv) Employment likely to be generated.

2. Purpose-wise break-up of the total land required:

3. Details of displacement of people due to the project, if any:
   (i) Number of families.
   (ii) Number of Scheduled Castes/Scheduled Tribe Families
   (iii) Rehabilitation plan. (to be enclosed)

4. Whether clearance under Environment (Protection) Act, 1986 required? (Yes/No)

5. Undertaking to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation and/of penal compensatory afforestation as well as cost for protection and regeneration of Safety Zone, etc. as per the scheme prepared by the State Government (undertaking to be enclosed).

6. Details of Certificates/documents enclosed as required under the instructions.

Signature
(Name in Block letters)
Designation
Address (of User Agency)

Date:-.....
Place:-.....

State Serial No. of proposal_____
(To be filled up by the Nodal Officer with date of receipt)

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)

State Serial No. of proposal_____

7. **Location of the project/Scheme:**

(i) State/Union Territory :

(ii) District. :

(iii) Forest Division :

(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) :

(v) Legal Status of forest :

(vi) Density of Vegetation. :

(vii) Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees (to be enclosed. In case of irrigation/hydel projects enumeration at FRl, FRl-2 mater & FRL-4 meter also to be enclosed.) :

(viii) Brief note on vulnerability of the forest area to erosion. :

(ix) Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest. :

(x) Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed). :

(xi) Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area-if so details thereof. :

(xii) whether any protected archaeological /heritage site/defence establishment of any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required. :

8. **Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 of Part-I is unavoidable and bares minimum for the project. If no. recommended area item-wise with details of alternatives examined.** :

9. **Whether any work in violation of the Act has bee carried out (yes/No). If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring officials. Whether work in violation is still in progress.** :

10. **Details of compensatory afforestation scheme.** :

(i) Detail of non forest area/degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches, size of each patch. :

(ii) Map showing non-forest/ degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries. :

(iii) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure etc. :

(iv) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme. :

(v) Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view. (To be signed by the concerned Deputy Conservator of Forests). :

11. **Site inspection report of the DCF (to be enclosed) especially highlighting facts asked in col. 7 (xi, xii), 8 and 9 above.** :

12. **Division/ District profile :**

(i) Geographical area of the district. :
(ii) Forest area of the district. :
(iii) Total forest area diverted since 1980 with number of cases. :
(iv) Total compensatory afforestation stipulated in the district/ division since 1980 on
(a) forest land including penal compensatory afforestation.
(b) non-forest land.
(v) Progress of compensatory afforestation: as on (date) _____on
(a) forest land
(b) non-forest land.

13. **Specific recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.** :

Date :_____
Place :_____

Signature
Name
Official Seal

PART-III

(To be filled by the concerned Conservator of Forests)

14. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forests (Yes/ No). If yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.

15. Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.

16. Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.

Date :_____
Place :_____

Signature
Name
Official Seal

PART-IV

(To be filled in by Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

Date : _____

Place : _____

Signature
Name & Designation
(Official Seal)

PART-V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

17. Recommendation of the State Government.

(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon).

Date :_____
Place :_____

Signature
Name & Designation
(Official Seal)

Instructions (for part-I) :-

1. The project authorities may annex a copy of the approved project/ plan in addition to filling Col. 1 (i) e.g. IBM approved mining plan for major minerals/ CMPDI plan with subsidence analysis report etc.
2. Map has to be in original duty authenticated jointly by project authorities and concerned DCF - Col. 1 (ii).
3. Complete details of alternative alignments examined especially in case of project like roads, transmission lines, railway lines, canals, etc. to be shown on map with details of area of forest land involved in each alternative to be given - Col. 1 (iii).
4. For proposals relating to mining, certificate from competent authority like District Mining Officer about non-availability of the same mineral in surrounding/ nearby non-forest areas.
5. In case the same company/ individual has taken forest land for similar project in the State, a brief detail of all such approvals/ leases be given as an enclosure along with current status of the projects.
6. The latest clarifications issued by the Ministry under Forest (Conservation) Act, 1980 may be kept in mind. In case information do not fit in the given columns, the same shall be annexed separately.

General Instructions :-

1. on receipt of proposal, Nodal Officer shall issue a receipt to the user agency indicating therin the name of the proposal, user agency, area in hectare, serial number and date of receipt.
2. If the space provided above is not sufficient to specify any information, please attach separate details/ documents.
3. While forwarding the proposal to the Central Government, complete details on all aspects of the case as per Form prescribed above read with the clarifications issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi should be given. Incomplete or deficient proposals shall not be considered and shall be returned to the State Government in original.
4. The State Government shall submit the proposal to the Central Government within stipulated time limits. In case of delay while forwarding, the reasons for the same to be given in the forwarding/ covering letter.

Annexure-II

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of ......

Office of the District Collector ......

****

No. ... Dated ......

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that...... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ...... (name of user agency) for .... (purpose for diversion of forest land) in .... district falls within jurisdiction of .... village(s) in ....tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire .... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...... annexure ....

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposal diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of .... villages(s) is enclosed as annexure ... to annexure......

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Annexure-I

FORM-I

(for linear projects)

Government of ......

Office of the District Collector ......

****

No ...

Dated.................

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that ...... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of .... (name of user agency) for .... (purpose for diversion of forest land) in .... district falls within jurisdiction of .... village(s) in ....tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire .... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...... annexure ....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)